लोकमत समाचार

तमसो मा ज्योतिर्गमय

{ दुनिया में सबसे सस्ती चीज है सलाह. एक मांगो, हजार मिलती है लेकिन सबसे महंगा है सहयोग, हजार से मांगो तो एक से ही मिलता है. ■ अज्ञात }

संपादकीय

एस्ट्रोसैट के जरिए भारत की ऐतिहासिक उड़ान

भारत ने खगोलीय शोध को समर्पित अपनी पहली अंतरिक्ष वेधशाला 'एस्ट्रोसैट' का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर इतिहास रच दिया. इस अभियान पर देश ही नहीं, बल्कि दुनियाभर की निगाहें टिकी थीं. 'एस्ट्रोसैट' पहला ऐसा मिशन है जिसे इसरो द्वारा एक अंतरिक्ष शाला के रूप में संचालित किया जा रहा है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो ने अपनी ख्याति के अनुरूप इस अभियान को बेहद कम बजट करीब 178 करोड़ रुपए में अंजाम दिया है. इसे अमेरिका के उपग्रह 'हबल' का भारतीय जवाब भी कहा जा रहा है. अमेरिका का 'हबल' दुनिया का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो अब तक आकाशीय ग्रहों का अध्ययन कर रहा है. इसका वजन 16,000 किलोग्राम है और इसकी लागत 100 अरब रुपए आई थी. इसकी तुलना में 'एस्ट्रोसैट' बेहद सस्ता और हल्का है. चीन भी अभी तक ऐसा नहीं कर पाया है. भारत अब अंतरिक्ष वेधशाला रखने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है. इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में 50 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं. यह पहली बार ही है कि अमेरिका ने अपने चार नैनो व्यावसायिक उपग्रहों को इसरो के माध्यम से प्रक्षेपित किया है. पीएसएलवी-सी 30 'एस्ट्रोसैट' के अलावा विभिन्न देशों के छह उपग्रह भी अपने साथ ले गया है. इस उड़ान का मकसद ब्रह्मांड की विस्तृत समझ विकसित करना है.'एस्ट्रोसैट' को पीएसएलवी-सी 30 रॉकेट के जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा. यह सुदूरवर्ती खगोलीय पिंडों के अध्ययन को समर्पित देश का पहला उपग्रह है. यह मिशन एक ही समय में अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल, लो एंड हाई एनर्जी एक्स रे वेवबैंड में ब्रह्मांड की निगरानी में सक्षम है. इस वेधशाला के निगरानी कार्यक्रम में देश के सभी प्रमुख खगोलीय संस्थान और कुछ विश्वविद्यालय शामिल हैं. देश इससे पहले 45 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित कर चुका है और इस पीएसएलवी-सी 30 की सफलता के बाद यह संख्या 51 हो जाएगी. हालांकि भारतीय खगोलविद दशकों से जमीनी दूरबीनों से आकाशीय हलचलों पर नजर रखते आए हैं, लेकिन अंतरिक्ष में अपनी वेधशाला होने से उनका काम और आसान हो जाएगा. पहली अंतरिक्ष वेधशाला के सफल प्रक्षेपण से भारत 'जी-5' में शामिल हो गया है. एस्ट्रोसैट अगले दो महीनों में पूरी तरह से कार्य करना प्रारंभ कर देगा और अगले पांच सालों तक जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा. निश्चित ही एस्ट्रोसैट के सफल प्रक्षेपण से खगोल विज्ञान के अनुसंधान की दिशा में वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिलेगी. इस ऐतिहासिक सफलता के लिए हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं. ■■

अपना ही दुश्मन

लघुकथा

चैतन्य त्रिवेदी

उस राज्य का रिवाज ही कुछ विचित्र था. वहां दुश्मन राज करते थे. जो दुश्मन नहीं है किसी न किसी का, वह राज्यकार्य के लिए सर्वथा अयोग्य समझा जाता. वहां अक्ल के दुश्मन राज करते थे. जो कानून का दुश्मन होता, वह कानून की हिफाजत का काम देखता. गरीबों का दुश्मन गरीबी हटाने के काम देखता था. इस तरह वहां रहने के नियम ही कुछ अलग किस्म के थे. आपको यह जाहिर करना जरूरी है कि आप किसके दुश्मन हैं. कुछ धर्म के दुश्मन, वे बड़े धार्मिक माने जाते. समाज के दुश्मन समाज-सुधारक. देश के दुश्मन, देशभक्त कहलाते. यानी कि हर क्षेत्र दुश्मनों से अटा पड़ा था. इस तरह वहां सारे दुश्मन मिलकर देश चला रहे थे. वे सारे दुश्मन चाह रहे थे कि हरेक को कहीं-न-कहीं दुश्मनी में संलग्न रहना जरूरी है. जो किसी का दुश्मन नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं. कई बेगुनाह इसी वजह से मारे जाते. वहां नागरिकों का सर्वे होता था और पसंदीदा दुश्मनी बतानी पड़ती. एक दिन राज्य के कारिंदे मेरे पास आए, पूछने लगे कि 'मैं किसका दुश्मन हूं.' मैंने कहा, 'मैं तो किसी का दुश्मन नहीं हूं' उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि एक हफ्ते के भीतर बता दूं या तय कर लूं कि मैं किसका दुश्मन हूं.

एक हफ्ते बाद मुझे राजा के दरबार में पेश किया गया ताकि मैं अभी भी बता दूं कि मैं किसका दुश्मन हूं. यह आखिरी मौका था. सब चुप बैठे थे. मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे बचा लूं अपना जीवन. किसका नाम लूं. मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था. राजा ने कहा, 'इतनी देर! इतनी देर में तो हम दुनिया को दुश्मन बना लें. कैसे डफर नागरिक हो तुम? आखिरकार मैंने चुप्पी तोड़ी. मैंने भरे गले से कहा, 'सरकार! मैं अपना ही दुश्मन हूं.'

हो-हो-हो!! क्या बात है. लाजवाब! पूरे दरबार में ठहाकों पर ठहाके लग गए. जिसने सुना वो हंस पड़ा. ■■

सत्तर वर्षीय हाथी की सवारी

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

हाथी की सवारी शानदार होते हुए भी आसान नहीं होती. संयुक्त राष्ट्र संगठन सत्तर वर्ष की सालगिरह मनाते समय 193 देशों का वजन संभाले हुए विशाल काया वाले 'सफेद हाथी' की तरह आगे बढ़ रहा है. इस हाथी के मूलभूत इरादों को कामयाब बनाने में भारत अहम भूमिका निभाता रहा है. इसलिए अब सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के हौदे पर बैठने के लिए उसके दावे में दम है. फिर भी पहले से हाथी पर सवार पांच 'महायोद्धा' आसानी से भारत को 'वीटो' के हथियार सहित अपने साथ बैठाने को तैयार नहीं होने वाले हैं. समय के साथ संयुक्त राष्ट्र के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव भले ही पारित हो गया, लेकिन सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता बढ़ाने के मुद्दे पर गोलमोल बात कही गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने नकली मुस्कराहट के साथ भारत के दावे का समर्थन कर देते हैं, लेकिन वीटो के अधिकार की बात पर उनके राजनयिक और नेता अंगूठा दिखाने लगते हैं. अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव देने से अब तक साथ देने वाला शक्तिशाली रूस रूठकर हाथ खींचने लगा है. चीन भी कूटनीतिक तरीके से भारत के साथ है. यह खींचतान महीनों ही नहीं बरसों तक चल सकती है. सुहाने सपने जल्दी पूरे भी नहीं होते. वहीं अनुभवी भारतीय राजनयिक इस व्यावहारिक पहलू पर भी ध्यान दिलाते हैं कि 'वीटो' के अस्त्र के बिना केवल मुकुट पहनकर हाथी पर बैठने से भारत सही अर्थों में महाशक्ति नहीं मान लिया जाएगा. वास्तव में इस हाथी पर अमेरिका ने अपनी दादागीरी बना रखी है. अमेरिका ने अपने निकटतम साझेदार इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करने वाले प्रस्तावों पर पिछले 33 वर्षों में 35 बार वीटो का इस्तेमाल किया. सुरक्षा परिषद के चार

> संयुक्त राष्ट्र संगठन सत्तर वर्ष की सालगिरह मनाते समय 193 देशों का वजन संभाले हुए विशाल काया वाले 'सफेद हाथी' की तरह आगे बढ़ रहा है.

अन्य सदस्यों ने 33 बरस की इसी अवधि में केवल 27 बार वीटो का उपयोग किया. हाल में रूस और चीन ने सीरिया में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के विरुद्ध वीटो का इस्तेमाल किया. इसलिए न्यूयॉर्क और सेन फ्रांसिस्को में जय-जयकार और 'प्यारे बराक' से गले मिलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धूमधाम के साथ आर्थिक संबंध अवश्य बढ़ा सकता है, 'मिस्टर सैम' की तरह हंटर नहीं थाम सकता.

संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में सुधार के लिए सुरक्षा परिषद के अलावा बुढ़ापे के साथ बिगड़ चुकी बीमारियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. शीर्षस्थ अंतर्राष्ट्रीय नेता और राजनयिक स्वीकार करते हैं कि संगठन में लालफीताशाही की बीमारी भयावह है और वित्तीय रुकावटों से विशालकाय शरीर ठीक से दौड़ नहीं पाता है. 1950 के बाद से अब तक संयुक्त राष्ट्र संगठन का खर्च चालीस गुना बढ़ चुका है. संगठन के तहत 17 विशेष एजेंसियां और 14 अंतर्राष्ट्रीय फंड काम कर रहे हैं. इन 17 विभागों में 41 हजार कर्मचारी हैं, जिस पर सालाना 5 अरब 40 करोड़ डॉलर खर्च होता है. संयुक्त राष्ट्र संगठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना में 1 लाख 20 हजार सैनिक तैनात रहते हैं. जिन पर नौ अरब डॉलर वार्षिक खर्च की व्यवस्था है. मजेदार बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन का वार्षिक बजट न्यूयॉर्क शहर के 75 अरब के सालाना बजट से भी आधा यानी करीब 35 अरब डॉलर के आसपास रहता है. यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की दौड़ में संगठन की चाल धीमी ही रहती है. इसी दृष्टि से आस्ट्रेलिया के पूर्व विदेश मंत्री गेरेथ इवांस ने पिछले दिनों स्पष्ट शब्दों में कहा कि ''संयुक्त राष्ट्र का गुणगान भले ही जोर-शोर से होता है, उसके कामकाज का ढर्रा बेहद निराशाजनक है.'' संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन की प्रमुख तथा न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क ने कुछ अर्से पहले स्वीकारा था कि ''संयुक्त राष्ट्र संगठन में अक्षमता तथा लालफीताशाही के कारण सही लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है.''

संगठन की एजेंसियों में तालमेल का अभाव है. एक ही काम के लिए कई एजेंसियां काम कर रही हैं. आजकल संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यावरण, जल तथा ऊर्जा पर बहुत बहस हो रही है. इन मुद्दों पर दुनिया के देशों में सहयोग तो दूर रहा, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में तालमेल नहीं है. पर्यावरण प्रबंध कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र की ही 30 एजेंसियां सक्रिय हैं. इसी तरह जल तथा ऊर्जा के प्रबंधन के लिए 20 एजेंसियों में अधिकाधिक फंड पाने की प्रतियोगिता - जोड़-तोड़ बनी रहती है. हम डिजिटल क्रांति लाना चाहते हैं. वहां संयुक्त राष्ट्र की हर एजेंसी के लिए आई.टी.सिस्टम अलग-अलग चल रहा है. संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक तिहाई काम लगभग 60 देशों में चल रहा है. हर एजेंसी का बजट करीब 20 लाख डॉलर है. उसी तरह लगभग 100 देशों में संयुक्त राष्ट्र के 1200 कंट्री ऑफिसर्स हैं. औसतन 10 कर्मचारी माने जा सकते हैं. अंतर्राष्ट्रीय कामकाज के लिए 80 से 90 लाख डॉलर का सालाना बजट है, जिसका आधा स्टाफ पर खर्च हो जाता है. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का वेतन ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तनख्वाह के बराबर लाखों डॉलर है. लेकिन शांति सेना के हर सैनिक को साल में औसतन 8,450 डॉलर की तनख्वाह मिलती है. दूसरी तरफ अमेरिका यूरोपीय समुदाय, जापान तथा आस्ट्रेलिया संगठन के बजट में कटौती और कर्मचारियों की छंटनी की मांग कर रहे हैं. ऐसी हालत में बूढ़ा हाथी कितना दौड़ेगा? ■■

ऐसे सुधरेगी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता

गुरचरण दास
लेखक और स्तंभकार

मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को यह सवाल पूछने से शुरुआत करनी चाहिए कि भारत के 15 साल की उम्र के जिन लड़के-लड़कियों ने एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा में भाग लिया था, उसमें किर्गिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देशों की तुलना में अंतिम से दूसरे स्थान पर क्यों आए? जी हां, वर्ष 2011 में आयोजित विज्ञान और गणित की साधारण परीक्षा में शामिल होने वाले 74 देशों में भारत के छात्रों का स्थान 73वां था. परीक्षा का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यक्रम (पीसा) द्वारा किया गया था और इस दुखद परिणाम पर तत्कालीन संप्रग सरकार की प्रतिक्रिया यह रही कि खराब प्रदर्शन के कारणों का पता लगाने की बजाय उसने परीक्षा में छात्रों के फिर से शामिल होने पर ही रोक लगा दी.

गरीब भारतीय माता-पिता क्यों इतने निराश होकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल रहे हैं, जो कि निःशुल्क है, और उन्हें फीस लेने वाले निजी स्कूलों में भेज रहे हैं? भले ही यह फीस कम हो, किंतु यदि वे अपनी गाढ़ी कमाई को बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, जो कि निःशुल्क उपलब्ध हो सकती थी, तो अवश्य ही ऐसा वे मायूसी में कर रहे होंगे.

दुर्भाग्य से समस्या 2009 में अधिनियमित शिक्षा का अधिकार कानून में निहित है. संप्रग सरकार ने मान लिया था कि समस्या स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या में निहित है. किंतु 2009 में 96.5 प्रतिशत बच्चे पहले से ही स्कूल जा रहे थे. समस्या गुणवत्ता की थी. शिक्षा का अधिकार कानून सीखने के परिणामों और शिक्षक गुणवत्ता पर पूरी तरह चुप है.

क्या किया जाना चाहिए? यह आश्वस्तिकारक बात है कि मंत्री ईरानी ने जनता के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है और सिस्टम को ठीक करने के बारे में सुझाव मांगे हैं. यहां छह ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिनके जरिए वे 24 करोड़ स्कूली बच्चों के भविष्य को बचा सकती हैं.

पहला, इस बात को समझें कि समस्या पैसे की नहीं, प्रबंधन की है. इस बात को लेकर आक्रोश मौजूद है कि स्कूलों में चार में से एक शिक्षक अनुपस्थित रहता है और उपस्थित रहने वाले हर दो में से एक शिक्षक स्कूल आने के बावजूद पढ़ाते हुए नहीं पाया जाता. संप्रग के शिक्षा विशेषज्ञ शिक्षा के दर्शन के बारे में बातें तो अच्छी करते थे, किंतु शिक्षकों की अनुपस्थिति जैसी वास्तविक समस्याओं को हल करने में वे बुरी तरह विफल रहे थे.

दूसरा, स्कूली शिक्षा नीति को बदलते हुए मात्रा की बजाय गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करें. गुजरात के गुणोत्सव कार्यक्रम को अपनाएं, जिसमें यह देखा जाता है कि बच्चे दैनिक आधार पर कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं. राष्ट्रव्यापी नियमित आकलन का तंत्र स्थापित करें. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का पूरी तरह से कायापलट कर इसे सीखने का एक पैमाना बनाएं.

तीसरा, महान नेता ही महान संस्थान बनाते हैं. इसलिए वरिष्ठता के आधार पर

> गरीब भारतीय माता-पिता क्यों इतने निराश होकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल रहे हैं?

प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति बंद करें. गुजरात के शिक्षा मॉडल का पालन करें और प्रधानाध्यापकों के चयन के लिए प्रधानाध्यापक पात्रता परीक्षा संस्थान बनाएं. स्कूल लीडर्स बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करें.

चौथा, पिछले वेतन आयोग के लागू होने के बाद शिक्षकों के वेतनमान में सुधार हुआ है. शिक्षण में बेहतर प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करें. तीसरे दर्जे के अध्यापक शिक्षण संस्थान (टीईआई) बनाने की बजाय भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का निर्माण करें.

पांचवां, निजी स्कूलों को परेशान न करें और न ही उन्हें दुधारू गाय समझें. 'लाइसेंस राज' से छुटकारा पाएं. इससे वास्तविक शिक्षा उद्यमी प्रोत्साहित होंगे.

छठवां, हमें चिली, सिंगापुर, स्वीडन, ब्राजील और पोलैंड की सर्वोत्तम शिक्षा पद्धतियों से सीख लेनी चाहिए. इनमें से कुछ देशों ने वैसी ही समस्याओं का सामना किया है, जैसी हम कर रहे हैं. उन्होंने अथक प्रयास से अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करके समस्याओं को हल किया है. उनसे हम सबक ले सकते हैं. ■■

अंतरिक्ष बाजार में भारत की बढ़ती धमक

शशांक द्विवेदी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

अंतरिक्ष से ब्रह्मांड को समझने और सुदूरवर्ती खगोलीय पिंडों के अध्ययन के साथ पृथ्वी का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के उद्देश्य से भारत ने अपने पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट पीएसएलवी-सी30 का सफल प्रक्षेपण किया. 513 किलोग्राम के एस्ट्रोसैट

> भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में कम संसाधनों और कम बजट में न सिर्फ अपने आप को जीवित रखा है बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है.

उपग्रह को 6 अन्य विदेशी उपग्रहों के साथ प्रक्षेपित किया गया. प्रक्षेपण के बाद इन सातों उपग्रहों को सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया गया.

'एस्ट्रोसैट' खगोलीय पिंडों के अध्ययन करने वाला भारत का पहला उपग्रह है. इस उपग्रह के सफलतापूर्वक लॉन्च के साथ इसरो ने कामयाबी का एक और मील का पत्थर स्थापित किया. इसके साथ ही पहली बार अमेरिका अपने सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए भारत की मदद ले रहा है जो अंतरिक्ष बाजार में भारत की धमक का स्पष्ट संकेत है. इसरो चेयरमैन ए. एस. किरन कुमार के मुताबिक, भारत 19 देशों के 45 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है और ये पहली बार है कि अमेरिका ने किसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए भारत की मदद ली है. अमेरिका 20वां देश है, जो कमर्शियल लॉन्च के लिए इसरो से जुड़ा है. भारत से पहले अमेरिका, रूस और जापान ने ही स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया है. वास्तव में विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती हुई ताकत को दर्शाता है. ये सफलता कई मायनों में बहुत खास है क्योंकि एक समय था जब भारत अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था और आज भारत विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है, जिससे भारत को वाणिज्यिक फायदा हो रहा है. इसरो की कम प्रक्षेपण लागत की वजह से दूसरे देश भारत की तरफ लगातार आकर्षित हो रहे हैं. इसरो द्वारा 45 विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से देश के पास काफी विदेशी मुद्रा आई है. इसके साथ ही लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के अंतरिक्ष बाजार में भारत एक महत्वपूर्ण देश बनकर उभरा है. चांद और मंगल अभियान सहित इसरो अपने 100 से ज्यादा अंतरिक्ष अभियान पूरे करके पहले ही इतिहास रच चुका है.

भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में कम संसाधनों और कम बजट में न सिर्फ अपने आप को जीवित रखा है बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है. भविष्य में अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. भारत द्वारा बड़े पैमाने पर इसका वाणिज्यिक उपयोग संभव है. ■■

नजर के पार

डिजिटल कूटनीति की ओर बढ़ता देश

रहीस सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान, अमेरिका के जिन दो छोरों पर भारत की प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है उसे भारत की राजनीतिक-आर्थिक कूटनीति की सम्बद्धता एवं सक्रियता के नए आयाम के रूप में देखा जा सकता है. न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में तो भारत का राजनीतिक नेतृत्व इससे पहले भी अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा चुका है लेकिन सैन जोस अब तक इससे वंचित था, जबकि वैश्वीकरण और तकनीकी युग के इस दौर में सैन जोस की महत्ता न्यूयॉर्क से कमतर नहीं आंकी जा सकती. यही कारण है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इस शहर के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के वैश्विक दिग्गजों से मुलाकात कर भारत को 21वीं सदी में दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने की राह में आगे ले जाने के लिए उनसे सहयोग का आह्वान किया और इस आह्वान का एक सकारात्मक असर भी दिखाई दिया. प्रधानमंत्री का यह प्रयास कितना सफल होता है, यह तो भविष्य पर निर्भर है, लेकिन क्या इस कदम को इस रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता है कि इन आयामों के जरिए भारत एक नई राह निर्मित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है?

प्रधानमंत्री की इस यात्रा को तीन खास विषयों के संदर्भ में देखा जा सकता है. प्रथम- संयुक्त राष्ट्र में सुधार और सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारतीय

राजनय संबंधी रणनीति. द्वितीय - सिलिकॉन वैली के दिग्गजों के समक्ष भारत के भविष्य की एक नई तस्वीर प्रस्तुत कर उनसे भारत के डिजिटल सशक्तीकरण में सहयोग का आह्वान और तृतीय आतंकवाद के विषय पर उन देशों को कठघरे में लाना जो इस पर एक विभेदकारी नजरिया रखते हुए इसे अच्छे और बुरे आतंकवाद में विभाजित कर दुनिया में एक भ्रम पैदा करने में सफल हो रहे हैं.

सैन जोस में प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य पर जिस प्रकार आश्वस्ति दिखी उससे यह अवश्य लगता है कि वहां उपस्थित दिग्गजों ने प्रधानमंत्री के प्रौद्योगिकी के रुझान को समझा और यह जानने में दिलचस्पी ली कि वे इसे किस तरह से देश के शहरों में विकास का अहम घटक बनाना चाहते हैं और साथ ही ग्रामों की इससे कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करना चाहते हैं. प्रधानमंत्री ने भविष्य की रूपरेखा पेश करते हुए डिजिटल खाई को पाटने का आह्वान किया. उनका मानना है जैसे-जैसे डिजिटल खाई पटती जाएगी वैसे-वैसे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन व प्रशासनिक बदलाव की संभावनाएं भी बढ़ेंगी. मार्क जुकरबर्क के कुछ सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना के साथ गवर्नेंस की जिन संभावनाओं को प्रस्तुत किया वे प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों के लिए भारत की नई तस्वीर पेश करने वाली साबित हुई प्रतीत होती हैं.■■

तोल बोल

नरेंद्र मोदी इवेंट मैनेजमेंट, पैकेजिंग और फोटो खिंचवाने के लिए मशहूर हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें अपने पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए. ■ शकील अहमद, कांग्रेस महासचिव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा समाप्त. यह सोचने का वक्त है कि देश को उनकी विदेशी यात्राओं से अब तक क्या मिला. ■ अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

© लोकमत समाचार
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
0712-2423527 (7 लाइन) 6618555
Email : lsedit.ngp@lokmat.com
advt.ngp@lokmat.com circ.ngp@lokmat.com

इतिहास पर नजर 30 सितंबर

आज ही के दिन 1994 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री टीए रेनॉल्ड्स और रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन की मुलाकात इसलिए टालनी पड़ी थी क्योंकि येल्तसिन विमान में सोते रह गए थे और आयरिश नेता को रूस के उप प्रधानमंत्री ओलेग सॉस्कोवेट्स के साथ मुलाकात से ही संतोष करना पड़ा था. हुआ यूं कि आयरिश प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी, दो मंत्री, कई सांसद और सेना का बैंड हवाई अड्डे पर येल्तसिन के विमान के उतरने का इंतजार कर रहे थे. करीब सवा घंटे तक आसमान में मंडराने के बाद येल्तसिन का विमान जब शैनन एयरपोर्ट पर उतरा तो इंतजार कर रहे आयरिश प्रधानमंत्री को बताया गया कि रूसी राष्ट्रपति बहुत थके हुए हैं, बीमार हैं और सो रहे हैं. बहरहाल येल्तसिन ने मॉस्को पहुंचने के बाद बताया कि वो सोते रह गए थे और सुरक्षा अधिकारियों ने लोगों को उन्हें जगाने नहीं दिया था. येल्तसिन ने ये भी कहा कि वो इस राजनयिक गलती के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर देंगे. ■■

- ■1681-नीदरलैंड एवं स्वीडन ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए.
- ■1687-औरंगजेब ने हैदराबाद के गोलकुंडा पर कब्जा किया.
- ■1882-एप्लेटन में विश्व का पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक ऊर्जा संयंत्र शुरू.
- ■1898-अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क की स्थापना हुई.
- ■1929-मनुष्य को ले जाने योग्य पहले रॉकेट ने उड़ान भरी.
- ■1958-फ्रेंच गुएना आजाद होकर गुएना गणराज्य बना.

पाठकों के पत्र

हिंदी को विश्व स्तर पर सम्मान दिलाएं

हाल ही में भोपाल में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ. इस सम्मेलन में विदेशों से आए प्रतिनिधियों ने फर्राटेदार हिंदी में भाषण देकर सबको चकित कर दिया किंतु हमारे ही देश के कई नेताओं को हिंदी नहीं आती. वे अंग्रेजी में ही भाषण देते हैं. आज अमेरिका व ब्रिटेन में कई विश्वविद्यालयों में संस्कृत व हिंदी पढ़ाई जा रही है. वहां के विद्यार्थी हिंदी में पीएचडी कर रहे हैं और हमारे ही देश में दक्षिण भारतीय लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं. यह हमारे देश के लिए शर्म की बात है.

■ एस.एस. सिंह, नागपुर

शिक्षकों की छंटनी

हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं प्राध्यापकों की संख्या में कमी की जाएगी. तात्पर्य अधिकांश कॉलेज बंद किए जाएंगे. कारण इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों की संख्या में कमी पाई गई. सच है शिक्षित बेरोजगारी की भयानक तस्वीर देश में बन रही है. भारतीय भाषा के शिक्षालयों में छात्रों की कमी देखने में आ रही है जहां शिक्षकों की छंटनी होने की संभावना है.

■ कमलेश मिश्र, चंद्रपुर

यही दो मसले हल न हुए...

कितना सुंदर लिखा है किसी ने...
प्यास लगी थी गजब की...मगर पानी में जहर था...!
पीते तो मर जाते और न पीते तो भी मर जाते...!

बस यही दो मसले,
जिंदगीभर हल न हुए...
न नींद पूरी हुई,
न ख्वाब मुकम्मल हुए...

वक्त ने कहा,
काश! थोड़ा और सब्र होता...
सब्र ने कहा,
काश! थोड़ा और वक्त होता...

सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए...
आराम कमाने निकलता हूं आराम छोड़कर!
'हुनर' सड़कों पर तमाशा करता है...
और 'किस्मत' महलों में राज करती है!

शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे ऐ जिंदगी,
पर चुप इसलिए हूं कि, जो दिया तूने...
वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता.